Funds for construction of Polyster X-ray Project

2010. SHRI S. MUTHUMANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that for the construction of new Polyster X-ray project, working capital to the tune of over Rs. 70 crores has been diverted from the Hindustan Photo Films, Nilgiri District, Tamil Nadu:

(b) whether it is also a fact that Government have offered 51 per cent shares to Du-pont of the new Polyster X-ray project;

(c) whether any demand has been received from the Hindustan Photo Films, Nilgiri District, to supply the Silver at the rate prevailing in the international Market; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) As per the assessment of Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Limited (HPF) a sum of about Rs. 45 crores has been diverted to the new polyester plant from the working capital of the existing plant.

(b) No, Sir.

(c) and (d) HPF has requested for duty free import of silver.

Modernisation of Leather Industry

2011. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI SURESH KALMADI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether India's Leather Industry has been asked to induct bio-technology and innovative leather processing techniques for a modernisation plant, designed to boost leather exports up to Rs. 10,000 crores by 2000 A.D., as repored in the Economic Times, New Delhi dated the 1st December, 1993;

(b) whether the Central Leather Research Institute (CLRI), Madras and the Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC), New Delhi, have called upon the Industry to reduce process costs by upgrading leather quality, turning tannery waste into wealth and selecting technology for optimum use of chemicals, energy and water used in leather processing;

(c) if so, what are the other details/outlines suggested by CLRI-TIFAC for the entire range of Indian leather industry;

(d) what is Governments reaction therefor; and

(e) what steps have been taken to boost leather exports during 1993-94?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) At a recently concluded workshop jointly organised by the Central Leather Research Institute (CLRI) and Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC) various technology aspects relating to structure of the industry, materials availability, technology support, marketing and exports, human resource development etc. were covered. Induction of biotechnology in the process of modernisation of leather industry was emphasised. An enzyme has recently been developed at Central Leather Research Institute, Madras for easy unhairing of raw hides and skins, totally avoiding use of polluting chemicals. It may take two-three year's time before the production of this enzyme is upscaled and made available to the industry. The need for optimisation in the use of chemicals, energy and water in leather processing was also stressed.

(c) The detailed results of this study are expected to be released to the Indian leather industry shortly.

(d) and (e) The Government of India is also implementating a comprehensive project for the growth of the leather industry in India with the financial assistance from the UNDP. Besides, the Council for Leather Export is implementing sub-subjects which aim at enhancing export capabilities of the Members of the Council.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को पुनः चालू किया जाना

2012. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग, कारपोरेशन रांची के पुनर्निर्माण संबंधी मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास अंतिम अनुशंसा किए जाने के लिए लंबित पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धन स्टेट बैंक और सरकार द्वारा किए गए तदर्थ आर्थिक उपायों के कारण कारपोरेशन की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उद्योग मंत्रालय द्वारा 31 अक्तूबर, 1993 तक कार्यान्वयन संबंधी पैकेज प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अंतिम अनुशंसा नहीं की जा सकी; और

(घ) सरकार कारपोरेशन का पुनर्वास करने और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही चलाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच० ई० सी०) घाटे वाली कंपनी होने के कारण, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित कर दी गई है।

(ख) एच० ई० सी० के निष्पादन में 1991-92 की तुलना में 1992-93 में सुधार हुआ है।

(ग) बी० आई० एफ० आर० से एक प्रचालन एजेन्सी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है जो एच० ई० सी० द्वारा प्रस्तुत टर्न अराउन्ड योजना की जांच कर सके।

(घ) सरकार कम्पनी को योजना और गैर-योजना निधियां देकर, बैंकों में नकद जमा सीमा बढ़ा कर और बेशी श्रमशक्ति को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना द्वारा युक्तिपरक बनाने इत्यादि के द्वारा इसकी सहायता कर रही है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को हुआ घाटा

2013. **श्री गया सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 के अक्तूबर माह तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हटिया को कुल कितना घाटा हुआ है? **उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्यमंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):** हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच० ई० सी०) को वर्ष 1993-94 में अक्तूबर तक 69.16 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

नई औद्योगिक नीति के अधीन स्थापित किए गए उद्योग

2014. **श्री गया सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति को लागू करने के बाद देश में अब तक स्थापित किए गए नए उद्योगों का ब्यौरा क्या है? **उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से नवंबर 1993 तक देश में विभिन्न उद्योगों की